

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
(1)	श्री श्याम सारी	आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3)	श्री मीर मजहर जली		सदस्य
(4)	श्री माता प्रसाद		सदस्य
(5)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्य
(6)	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
(7)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8)	श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(9)	श्री आर०सी०मंगल	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रूढ़ी के प्रतिनिधि)	सदस्य
(10)	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबंध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(11)	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1-	दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(1)/84	परिषद की दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 11-11-83 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/84	परिषद द्वारा दिनांक 11-11-83 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- सुरदाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी आवास आयुक्त ने परिषद को कराया। निर्णय लिया गया कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुलिस कर्मियों में परिषद के आवास गृहों की शीघ्र खाली कराया जाय और इस बीच उन्के द्वारा किये गये अनाधिकृत अध्यासन के संदर्भ में किराये की धनराशि वसूली की जाये। 2- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग सम०ए०/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के स्तर पर सम्पन्न कार्यवाही शीघ्र पूरी कराकर उनकी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

- 3- परिषद द्वारा निर्मित कालोनीज को स्थानीय सिकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रदत्त कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत तथा तथ्यात्मक टिप्पणी परिषद के पूर्व नियमानुसार शीघ्र तैयार कराकर आवास आयुक्त/ अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये।
- 4- रानीखेत में परिषद की योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में लिखे गये पूर्व नियमानुसार आवास आयुक्त सेन्ट्रल कमान्ड के उच्चाधिकारियों तथा केप्टोनेट बोर्ड के अध्यक्ष से संबंध कर केप्टोनेट बोर्ड के क्षेत्र के भीतर भूमि प्राप्त करने का प्रयास करें।

3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।

प्रथम/(3)/84

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार-विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिखे गये:—

- 1- वर्ष-1983-84 के लिये निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद को यह बताया गया कि बनपुर तथा ताराणसी में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों की नियुक्तियाँ तो हो गयी हैं किन्तु सम्बन्धित रेकॉर्ड्स के हस्तान्तरण न होने के कारण तथा नियुक्त अधिकारियों के साथ सम्बद्ध सभी स्टाफ की नियुक्ति न होने के कारण यह अधिकारी भी प्रभावी ढंग से कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाये हैं। निर्णय लिया गया कि नई योजनाओं के लिये अधिग्रहीत की जा रही भूमि का कच्चा शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाये और साथ ही साथ कच्चा प्राप्त भूमि का अधिनिर्णय तैयार कराने एवं प्रतिकर बंटवारे का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाय ताकि अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।
- 2- बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष-83-84 में 802-94 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध नवम्बर-83 तक 56 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। 1191.96 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि इटों के उत्पादकों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण इटों की उपलब्धता माँग के अनुसार नहीं हो पा रही है और यदि इस संबंध में शासन स्तर से शीघ्र निर्णय नहीं होता है तो निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो पायेगा। विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इटों की उपलब्धता के आधार पर वे विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जायें जिससे पूर्ण किये गये भवनों का अर्जिटन शीघ्र किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में इटें उपलब्ध होने पर नये क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाये।
- 3- 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद द्वारा पूर्व में 10500 दुर्बल आयु वर्ग/ साइट स्प्लिट सविसेज इकाइयों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित कठिनाइयों के कारण परिषद की क्विली बैठक में पुनरीक्षित कर 8500 दुर्बल आयु वर्ग/साइट स्प्लिट सविसेज के पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक के समय बताया गया कि कई योजनाओं की भूमि का प्रतिकर न बंटने एवं भूमि पर न्यायालय से स्वयं आदेश प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सभी लक्ष्य पूर्ण भवनों का नहीं है। इनमें पूर्णतः एवं प्रगति पर दोनों प्रकार के भवन हैं।

यह भी बताया गया कि इटों की उपलब्धता में कमी होने के कारण जो भवन प्रगति पर है उन्हें पूर्ण करना तथा जिसे भूमि पर कोई विवाद नहीं है वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई हो रही है जिसे 8500 को पुनर्रचित तथ्य की पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी। भूमि सम्बन्धी कठिनाई एवं इटों की उपलब्धता के स्थिति को देखते हुये निर्णय लिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक भवन पूर्ण करने अथवा प्रगति में लाने का प्रयास किया जाये तथा निर्धारित तथ्य की पूर्ति में जो कमी रह जाये उसे अगले वित्तीय वर्ष के तथ्य शामिल करके 83-84 के तथ्य निर्धारित किये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियन्ता/अधीनस्थ अभियन्ता जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से अर्थ से संबंध स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि जिन योजनाओं में प्रतिकार न बटने एवं भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकार न लेने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है उनमें पुलिस बल की सहायता से रेलों की फसल के बाद तुरन्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। इस हेतु पुलिस बल प्राप्त करने के लिये अगले तिथियों निर्धारित करावें जायें और निर्धारित तिथियों को सम्बन्धित अधीनस्थ अभियन्ता भी कार्य स्थल पर उपलब्ध रहे। इस संदर्भ में अधीनस्थ अभियन्ता एक निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम बनवायें और यदि पुलिस बल एवं जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसकी सूचना अवगत आदुक्त को दें।

- 4- परिषद को वर्ष-76-77 व 77-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अतिरिक्त उपलब्ध न होने के बारे में की गयी जानकारी की जानकारी परिषद को करायी गयी। निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों से विवरण प्राप्त हो गये है उसी के आधार पर वर्ष-76-77 व 77-78 के बैंक समाधान का कार्य व बलेसशोट बनाने का कार्य अप्रैल, 84 तक अवश्यमेव पूर्ण कर लिया जाये।
- 5- वित्तीय वर्ष-75-76 तथा 76-77 के पक्के चिट्टे जिसका स्थापना हिन्दी में लिया जा चुका है उसे रूपवाकर जनवरी-84 के अन्त तक विधान मण्डल के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने हेतु शासन को अवश्य भेज दिया जाये।
- 6- वर्ष -77-78 से 82-83 तक की बलेसशोट को अंतिम रूप देने के लिये जो समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसकी प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। निर्णय लिया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दशा में वर्ष-77-78 की बलेसशोट अप्रैल-84 के अन्त तक अवश्य तैयार करली जाये।
- 7- नगरवार आर्बोर्ट सम्पत्तियों को मार्च-82 तक के मूलधन एवं व्याज की गणना की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में बताया गया कि राजाजीपुरम की 500 सम्पत्तियों का विवरण अपूर्ण होने के कारण उनका व्याज एवं मूलधन की गणना मन्थालय से नहीं की जा सकी एवं सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, राजाजीपुरम सम्बन्धित अभिलेखों को पूर्ण कराकर उनके मूलधन एवं व्याज की गणना अपने स्तर से करायेगे।

निर्णय लिया गया कि इन्दिरानगर योजना से सम्बन्धित कार्य जो प्रगति पर है उसे प्रत्येक दशा में जनवरी, 84 तक पूर्ण करा लिया जाये और यह सुनिश्चित कराया जाये कि वित्तीय वर्ष-82-83 से सम्बन्धित मूलधन एवं व्याज की गणना सभी सम्पत्ति प्रबन्ध केसालिय अटिलेख अपने स्तर पर करावें। इस सम्बन्ध में सहित सूचना परिषद को अगली बैठक में रखी जाये।

- 11- जोधाबाई मेमोरियल ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा। प्रथम/(11)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से जोधाबाई मेमोरियल ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा का परिष्कार किया गया।
- 12- हिल्टन मेन विस्तार योजना, लखनऊ का भाग-33 का प्रस्ताव। प्रथम/(12)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि यदि वांछित अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत कर नहीं मिलती है तो भवन का निर्माण ही बनाया जाये।
- 13- उ०प्र०जावास एवं विकास परिषद भूखंडों तथा भवनों के पुनर्निर्माण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 के विनियम 3 परिभाषा (1) (प) में एक अतिरिक्त परा जोड़ने के सम्बन्ध में। प्रथम/(13)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि प्राथमिक विधायकों के साथ साथ उच्च स्तर के विधायकों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी यह सुविधा अनुमत्त कर दी जाये और तदनुसार विनियम-3 (1) में संशोधन किया जाये।
- 14- विनियम-28(3) में संशोधन किया जाना। प्रथम/(14)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 15- विनियम-3(5) में प्रयोग के प्राविधान का संशोधन। प्रथम/(15)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 16- परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/वर्कवाज कर्मचारियों से असिस्टेंट ग्रेड-III वेतनमान 30,360-550 के घटी पर चर्चा। प्रथम/(16)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि रिक्तियों की सूचना देवायोजन कार्यालय को भी दे दी जाये और इसी से आवश्यक संख्या में नाम भगाकर परीक्षाओं आयोजित की जाये और चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाये।
- 17- उ०प्र०जावास एवं विकास परिषद में कार्यरत विधुत/यांत्रिक अभियन्ताओं को सिविल अभियन्ताओं के समान वेतनमान वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में। प्रथम/(17)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि विधुतीकरण कार्य हेतु परिषद में कार्यरत विधुत/यांत्रिक अभियन्ताओं को वही वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकार प्रदान कर दिये जाये जो परिषद के सिविल अभियन्ताओं को प्राप्त है परन्तु विधुतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्ताव एवं डिजाइन इत्यादि का अनुमोदन अधीनस्थ अभियन्ता स्तर के अधिकारों से प्राप्त करने के उपरान्त ही अधीनस्थ अधिकारों प्रदत्त वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत करेंगे।
- 18- परिषद के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों के लिये प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में। प्रथम/(18)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक टेंडर डिजाइन का यूनिट प्राकल्पन तथा डिजाइन इत्यादि अधीनस्थ अभियन्ता स्तर के अधिकारों से अनुमोदित होने के उपरान्त ही अधीनस्थ अधिकारों प्रदत्त वित्तीय एवं प्राविधिक अधिकारों का प्रयोग अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत करेंगे।
- 19- लखनऊ में एक परिकल्पना बूत एवं लखनऊ तथा बरेली में एक एक परिकल्पना बूत के सृजन के सम्बन्ध में। प्रथम/(19)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
20-	परिषद योजनाओं में बुकारोपण की प्रगति।	प्रथम/(20)/84	बुकारोपण की प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी।
21-	परिषद योजनाओं में आवंटित धन भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण कराये जाने पर भवन सामग्री समब शुल्क तथा जस व्यय शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
22-	राजजोपुरा में योजना भवन-2 के सेक्टर-2 एवं 19 में कुल 74 दुकानों 24 घरे सड़कती एवं 44 दुकानों 8 घरे सड़कती का निर्माण परिषद फंड से।	प्रथम/(22)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
23-	बुन्द शेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव में 17 दुकानें एवं 2 विद्यालय का परिषद फंड से निर्माण।	प्रथम/(23)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	भवनों में अतिरिक्त निर्माण (विस्तार) हेतु मानचित्रों का विक्रय।	प्रथम/(24)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना-आबाद मार्ग, लखनऊ।	प्रथम/(25)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	देहरादून में राजपुर रोड पर ग्राम-आवास में राजपुर रोड ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, देहरादून को धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(27)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	विश्वनाथ रोड ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-एफ-2 अल्मोड़ा का संशोधित धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्रशासनिक प्राक्कलन।	प्रथम(28)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	विश्वनाथ रोड ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 अल्मोड़ा का संशोधित धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राथमिक प्राक्कलन।	प्रथम/(29)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	सेण्टल सड़क मार्ग ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना जगुमगाँव का धारा-28 का प्रस्ताव।	प्रथम/(30)/84	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।
31-	देहरादून रोड योजना सं०-1 का विस्तार ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना इडकी को धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(31)/	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

- 32- हरिद्वार नगर तृतीय विस्तार योजना, कैलाशवाट मार्ग, लखनऊ। प्रथम/(32)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 33- वर्ष-1980 में परिषद के फिरोज गान्धी नगर आवास योजना रायबरोली में निर्मित भवनों में व्याप्त अवतराजों के आवास आशुक्त के आदेश सं०-1306/प्रशा० एक दिनांक 14 जुलाई, 1983 द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री विद्यार्थी राय, सहायक अभियन्ता द्वारा दि० 7-10-83 को प्रेषित अपील को सुनवाई के प्रसंग में। प्रथम/(33)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्तुदर्थ गठित उप समिति के समक्ष इस अपील को रखा जाये और उसकी आख्या परिषद को अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
- 34- गौला गोकर्ण नाम भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के सम्बन्ध में। प्रथम/(34)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
- 35- मेरठ नगर योजना सं०-1 देहरादून को कूटी ए-ई भूमि की धारा-28 को प्रस्ताव एवं प्राकल्पन। प्रथम/(35)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 36- विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1, अयोधा की धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राकल्पन। प्रथम/(36)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 37- हरिद्वार में कनार रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना कन्था गोकुल कनार हरिद्वार की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राकल्पन। प्रथम/(37)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 38- परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष विद्वत्जी (अब वि० नि० 30-7) लखनऊ के अन्तर्गत स्थापित भूद्वारा-गृह से 564 बोरी सोमेट की जमी के लिये उत्तर-दायी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आवास आशुक्त के आदेश सं०-1184/प्रशा० एक दिनांक 7 जुलाई, 83 के द्वारा पारित दण्ड के विरुद्ध श्री विद्यार्थी राय सहायक अभियन्ता को अपील को सुनवाई के प्रसंग में। प्रथम/(38)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्तुदर्थ गठित उप समिति के समक्ष इस अपील को रखा जाये और समिति को आख्या परिषद को अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
- 39- परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को विवाहा पदधति पर आवंटित भवनों में अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में। प्रथम/(39)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 40- परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के निर्माण एवं विकास कार्य के लिये अतिरिक्त वृत्त/क्षेत्र स्टाफ की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में। प्रथम/(40)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
41-	वास्तुकला एवं निषीजन • अनुभाग का पुनर्गठन।	प्रथम/(41)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
42-	गोष्ठा गिर्द भूमि विकास • एवं गृहस्थान योजना, गोष्ठा में विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(42)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
43-	परिषद योजनाओं में शिक्षण • संस्थाओं तथा अन्य धार्मिक परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं में भूमि का मूल्य निचे जाने के विषय में।	प्रथम/(43)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्णय लिया गया कि इन्हें सुविधा धार्मिक अस्पतालों को अनुमत्त न की जाये। बहर भी निर्णय लिया गया कि भूमि का जाधा मूल्य कब्जा लेने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लिया जाये और शेष मूल्य 4 वर्ष के भीत 8 8 माहों किरतों में वसूल किया जाये।
44-	गाजियाबाद हाफुड मार्ग • एवं हासना दिल्ली लार्ड प्रास मध्य योजना सं०-1 गाजियाबाद (क्षेत्रफल 660 एकड़ अनुमानित लागत ₹ 18.50 करोड़)	प्रथम/(44)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
45-	परिषद में दि० 1-6-81 के पश्चात् कार्यरत कार्य- प्रधारित कर्मचारियों के नियमितकरण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(45)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	दोहरीघाट रोड भूमि • विकास एवं गृहस्थान योजना-आजमगढ़।	प्रथम/(46)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से बहर निर्णय लिया गया कि अधिग्रहीत भूमि का स्वामित्व मूल भू-स्वामियों को उसी स्थिति में हस्तान्तरित किया जाये जब कि वह स्थाय एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क बहन काने के लिये तैयार हो।
47-	मसौली भूमि विकास एवं • गृहस्थान योजना सं०-4 भाग-2 की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(47)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
48-	मसौली बजार भूमि • विकास एवं गृहस्थान योजना, देवरिया।	प्रथम/(48)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
49-	पैसार भूमि विकास एवं • गृहस्थान योजना, सं०-2 जोराबकी (क्षेत्रफल 127.00 एकड़)	प्रथम/(49)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति को संस्तुति का अनुमोदन किया गया।
50-	भूमि विकास एवं गृहस्थान • योजना (रासघाट रोड) अलीगढ़ की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(50)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
51-	भूमि विकास एवं गृहस्थान • योजना सं०-1 टनलपुरा की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	प्रथम/(51)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

- 2
- 3
- 4
- 52- सीतापुर नगर के पास कपारथला ग्राम विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर को धारा-28 के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के संक्षेप में। प्रथम/(52)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 53- वि० नि० कार्यों को कारखानों में परिवर्तित करने हेतु परिषद के विचारार्थ व्याख्यात्मक रिपोर्ट। प्रथम/(53)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 54- इन्दिरा नगर देहरादून में स्थित ऐसे गृहों जिन्हो अव्यवहृत हये 10 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है पर भवन निर्माण हेतु समझवृद्धि के संक्षेप में। प्रथम/(54)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 55- इन्दिरानगर योजना के सेक्टर-5 में बाबा गुरुनाथ आश्रम में बना दूबानों को कम्पाउन्डिंग क्षेत्र तथा परिषद क्षेत्रों में अधिग्रहण से मुक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से किये निर्माण के विषय में। प्रथम/(55)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस भूमि पर बाबा गुरुनाथ आश्रम द्वारा व्यवसायिक निर्माण किया गया है उसे परिषद की संघर्ष योजना के अनुसूची के अनुसार आवश्यक हो माना जाय और वर्तमान आवश्यक दर ₹ 150/= प्रति वर्गमीटर की दर से कुल 1960.125 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग हेतु 294123.75 ₹ कम्पाउन्डिंग फीस तथा ₹ 1000 बिना स्वीकृति निर्माण करने के लिये अर्थात् कुल ₹ 2,95,123.75 (दो लाख नौसत्तानवे हजार एक सौ लेखस पञ्चहत्तर पैसे) प्राप्त कर कम्पाउन्डिंग कर दी जाये।
- 56- उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा पत्र अष्टम श्रृंखला का निर्गत किया जाना। प्रथम/(56)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 57- मुख्य अर्थसचिव/विभागीय निमित्त इकाई से एक एक नो० सि० तथा निम्न अर्पी सिपिट के पद समर्पित किये जाने के संक्षेप में। प्रथम/(57)/84 परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
- 58- विद्युत सप्लाइ विद्युत मेरठ के एक लोडजत जीप/टैक्सी उपलब्ध कराने हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक रिपोर्ट। प्रथम/(58)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
- 59- परिषद की गाड़ियों के निष्प्राप्य घोषित करने के लिये परिषद की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक रिपोर्ट। प्रथम/(59)/84 परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

पुत्र का/राधा

31/3/84

24-3-84